

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3638
दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

3638. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत दस वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) का निर्माण किया गया है;
- (ख) विगत दस वर्षों के दौरान एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान को कितनी निधि आवंटित की गई है; और
- (ग) एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान के उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के नाम क्या हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): हेल्थ डायनमिक्स ऑफ इंडिया (इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोसिज़), एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य सेवा प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। राजस्थान सहित देश भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ख): पिछले दस वर्षों के दौरान एनएचएम के तहत राजस्थान को जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

राजस्थान के उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों सहित देशभर में ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा एनएचएम के तहत की गई विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, निःशुल्क डायग्नोस्टिक्स सेवा पहल और निःशुल्क दवा सेवा पहल, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के तहत विभिन्न कार्यकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता प्रदान करना है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से पांच वर्ष (2021-2026) की अवधि में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राजस्थान राज्य को केंद्र द्वारा जारी राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	केंद्र द्वारा जारी राशि
1	2014-15	1,168.46
2	2015-16	1,329.48
3	2016-17	1,234.18
4	2017-18	1,615.29
5	2018-19	1,667.00
6	2019-20	1,781.83
7	2020-21	2,000.58
8	2021-22	1,924.95
9	2022-23	1,460.80
10	2023-24	2,785.46

नोट: उपरोक्त जारी राशि केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
